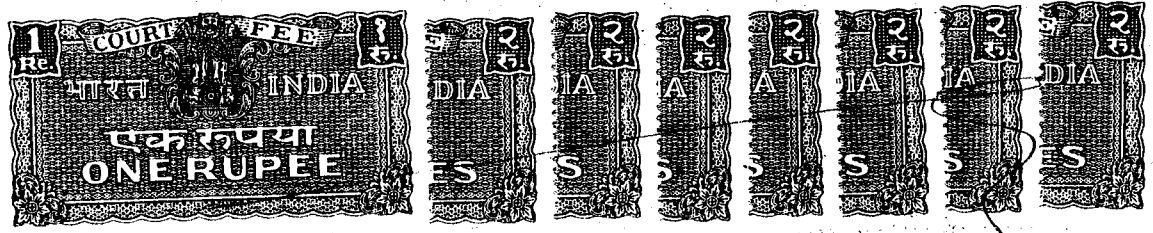


Admit-
Nm App + Recd

58

मान्नीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर



बेजनाथ पटेल मृतक द्वारा वारिश्मान-

- 1- पीताम्बर प्रसाद पटेल उम्र 63 वर्ष,
 - 2- नन्दलाल पटेल उम्र 56 वर्ष,
 - 3- इन्द्रबसुआ विधवा पत्नी शिवराम पटेल निवासी ग्राम दनगल तहसील मऊंज जिला रीवा म०प्र०
- दोनों के पिता बेजनाथ पटेल सा० भलुआ तह० मऊंज जिला रीवा म०प्र०

सनत कुमार पिता सत्यभारण पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खैरा जनकेश्वर तहसील मऊंज जिला रीवा म०प्र०

सरजो मृतक द्वारा वारिश्मान-

- 5- रामसिया पटेल उम्र 65 वर्ष
 - 6- भैरालाल पटेल उम्र 56 वर्ष,
 - 7- हरि प्रसाद पिता जनकी उम्र 40 वर्ष तीनों निवासी ग्राम भलुआ धाना नरगढी तहसील मऊंज जिला रीवा म०प्र०
 - 8- श्रीमती सुगनी पत्नी रामखेलावन ग्राम दनगल तहसील मऊंज जिला रीवा म०प्र०
- पिता सरजो
- आवेदक गण

बनाम

- 1- शोभनाथ तनय अयोध्या प्रसाद कर्मी
- 2- बड़ी प्रसाद तनय रामदुलारे निः संतान मृतक विलोपित
- 3- शोभनाथ तनय रामदुलारे कुर्म० सा० भलुआ
- 4- राजमीण पिता गजाधर कुर्म०
- 5- सीताराम तनय जगन्नाथ गजाधर कुर्म०
- 6- श्रीमती करम पत्नी सीताराम

R 1670-12/08
3-2-08
शरा आत्र दि० 30-12-08
बनाम मण्डल म० प्र० ग्वालियर

30/12/08

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1670-चार/2008

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-3-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 161/अपील/85-86 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2008 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क मुख्य रूप से तर्क दिया है कि आवेदक बैजनाथ पटेल और एवं सरजू ने विचारण न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर आवेदकगण के पिता बैजनाथ व सरजू के नाम आदेश दिनांक 4-5-84 को नामांतरण आदेश पारित हुआ। जिसके विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 25-9-85 को निरस्त की गई। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की गई जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30-10-08 को अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी आधार लिया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समय-सीमा पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में</p>	

गुण-दोषों के आधार पर द्वितीय अपील में निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।


3/ अनावेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदकगण के पिता बैजनाथ एवं सरजू ने अनावेदिका नोहरी के वारिसों शोभनाथ व छोटेलाल को उनकी भूमि से संधित विवाद होने के कारण हाल में पक्षकार बनाया है। नोहीद के वसीयतनामा के आधार पर छोटेलाल व शोभनाथ के नाम 6 कित्ता भूमियों का नामान्तरण हो गया था। यह भी तर्क दिया कि नोहरी ने आवेदक सरजू व बैजनाथ के विरुद्ध दावा किया था जिसमें अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया। उक्त व्यवहारवाद राजीनामा के आधार पारित आदेश अनावेदक के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर सरजू एवं बैजनाथ को कोई हक प्राप्त नहीं हुआ। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त ने प्रकरण को गुण-दोष पर निराकरण करने के बाद प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त के आदेश से जो भी वारिसान बैजनाथ व सरजू के हैं उन्हें तहसील न्यायालय में पूर्ण सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक के आवेदन पर नामान्तरण आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि

व्यवहार न्यायालय से आवेदकगण के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया है जबकि विचारण न्यायालय ने आवेदकगण के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किये हैं और प्रकरण विचारण न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर गुण-दोषों पर आदेश पारित करें। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती हैं। जहां तक आवेदक अभिभाषक उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया है, उचित नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण एवं उनके अभिभाषक लगातार उपस्थित होते रहे। उनके द्वारा पक्षकारों की मृत्यु की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण में यह आधार नहीं लिया जा सकता कि आधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया है। चूंकि यह प्रकरण भूमि के नामांतरण से संबंधित है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित किया है और प्रत्यावर्तित प्रकरण में सभी वारिसों को रिकार्ड पर लिया जाकर उभय पक्ष की सुनवाई की जायेगी। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण में यह आधार नहीं लिया जा सकता कि आधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश होने से निरस्त किया जा जाये। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त का आदेश कोई अंतिम आदेश नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त ने प्रकरण को विचारण न्यायालय उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का

अवसर देकर गुण-दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30-10-08 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


(एस0एस0 अली)
सदस्य

M